महोदया, आपने मुझे विशेष उल्लेख के तहत बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं । धन्यवाद ।

SHRI SARADA MOHANTY (Orissa): I would like to associate myself because Orissa is also producing coal. So, Orissa is also having the same problem.

**Demand to Hand over Dabolim Airport (Goa) to Civilian Authorities**

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): I want to draw the attention of the Prime Minister to the Dabolim Airport in Goa. This Airport in Goa is being manned and managed by the Indian Navy. They have an institute, INS Hansa, which is an Air Unit of the Navy. This is a very congested airport for civilian traffic. The Southern Command of Navy is stationed in Cochin, which is barely one hour away from Goa by air, We are also going *to* have a new base seaward at Karwar. I feel this Airport is totally mismanaged by the Navy. Under the Civil Aviation rules no high rise buildings are allowed around the periphery of the Airport. Since this land is under the control ol the Navy, there is a lot of malpractice and new high-rise buildings are being permitted to be constructed around the Airport. The biggest tragedy is that we have gaint petlletisation plant and a fertiliser plant with all agrochemicals in the approach of the Airport. Parallel to the Airport we have the Naphtha pipeline taking chemicals from the Port to this Plant. It is just like a time bomb and it may explode any time. We are having more than 20 chartered flights per week and almost one hundred domestic flights landing at the air port. Goa i» an international destination for tourists. Every hour we have a flight. This Airport is totally mismanaged because this is under the control of the Navy. It will be appropriate that this Airport is handed over to the civilian authorities, because there is hardly any Naval traffic. All the planes from this Airport have been shifted either to Madras, or to Cochin or to other airfields. I hope the Prime Minister will take this very seriously and see that this airport is handed over to the civilian authorities.

Madam, we have spent a lot of money here and still the work to expand the Airport is going on. We are going to have the civilian terminal at a cost of Rs. 9 crores. Madam, at the same time, we are violating the basic ]aw» of civil aviation. At the Goa runway two roads are crossing. Nowhere else this is permitted. This has been made possibla because it is under the Defence. I request that these roads should be removed. There should be a gate for th« Naval authorities to pass by. away from the runway. I hope the hon. Prima Minister will give serious attention to it and see that this airport is transferred to the civil authorities.

**Demand for Providing Drinking Water in Central and South Bihar.**

श्री जलालुद्दीन अन्सारी (बिहार) : मैडम, मैं आपके माध्यम से बिहार की जो प्यासी जनता है उसके दुखदर्द की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अभी मध्य और दक्षिण बिहार में हर जगह पीने के पानी की कमी है, पेय जल का अभाव है । राज्य सरकार के पास धन नहीं है कि वह इस दिशा में प्यासी जनता की भरपूर मदद कर सके। यह कोई एक साल का सवाल नहीं है । पिछले कई वर्षों से जब गर्मी का मौसम आता है तो मध्य और दक्षिण बिहार में पीने के पानी का संकट पैदा हो जाता है । हमारे माननीय मंत्री जो बिहार से सम्बंध रखते हैं श्री रामेश्वर ठाकुर जी उनसे भी खास तौर से मैं यह कहना चाहूंगा कि आप बिहार में इस समस्या के हल के लिए केन्द्र सरकार की ओर से बिहार सरकार को आर्थिक मदद करें आवश्यक सहायता दें और दोनों

सरकारें मिल करके इस पेय जल संकट के समाधान के लिए कोई ठोस कदम उठायें। इस गर्मी में प्यासी जनता को अगर पानी नहीं मिल पाता है तो आप आसानी से समझ सकतीं हैं कि इस गर्मी में बिना पानी के कैसे लोग रह सकते हैं। यह पुरानी कहावत है कि जल ही जीवन है और जब जल ही नहीं है तो जीवन क्या है। इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यह मांग करता हूं कि इस गम्भीर मसले पर तत्काल बिहार सरकार से राय करके उनको आवश्यक मदद करके पीने के पानी की व्यवस्था मध्य और दक्षिण बिहार में करने की दिशा में अविलम्ब कदम उठायें। यह आपसे निवेदन है।

شری جلال الدین انصاری (بہار): میڈم، میں آپ کے مادھیم سے بہار کی جو پیاسی جنتا ہے اس کے دکھ درد کی اور سرکار کا دھیان آکرشت کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی مدھیہ اور دکشن بہار میں ہر جگہ پینے کے پانی کی کمی ہے۔ پینے جل کا ابھاؤ ہے۔ راجیہ سرکار کے پاس دھن نہیں ہے کہ وہ اس دشا میں پیاسی جنتا کی بھرپور مدد کر سکے۔ یہ کوئی ایک سال کا سوال نہیں ہے۔ پچھلے کئی ورشوں سے جب گرمی کا موسم آتا ہے تو مدھیہ اور دکشن بہار میں پینے کے پانی کا سنکٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے سامنے منتری جو بہار سے سمبندھ رکھتے ہیں شری رامیشور ٹھاکر جی ان سے بھی خاص طور سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ بہار کی اس سمسیا کو حل کرنے کے لیے کیندر سرکار کی اور سے بہار کو آرتھک مدد دیجیے۔ آوشیک سہائتا دیجیے اور دونوں سرکاریں مل کر کے اس پینے جل سنکٹ کے سمادھان کے لیے کوئی ٹھوس قدم اٹھائیں۔ اس گرمی میں پیاسی جنتا کو اگر پانی نہیں مل پاتا ہے تو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس گرمی میں بنا پانی کے کیسے لوگ رہ سکتے ہیں۔ یہ پرانی کہاوت ہے کہ جل ہی جیون ہے۔ اور جب جل ہی نہیں ہے تو جیون کیا ہے۔ اسی لیے میں آپ کے مادھیم سے کیندر سرکار سے یہ مانگ کرتا ہوں کہ اس گمبھیر مسئلے پر تتکال بہار سرکار سے رائے کر کے ان کو آوشیک مدد کر کے پینے کے پانی کی ویوستھا مدھیہ اور دکشن بہار میں کرنے کا اولمب قدم اٹھائیں۔ یہی آپ سے نویدن ہے۔

श्री नरेश यादव : महोदया, मैं भी इससे अपने को सम्बद्ध करता हूं :

THE DEPUTY CHAIRMAN; The House is adjourned till 2.30 P.M.

The House then adjourned past one of the clock. for lunch at seventeen minutes

The House reassembled after lunch at thiny-three minutes past two of the clock

The Vice-Chairman (Shri Md. Salim) in the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM); Private Members' Resolution. Shri Suresh Pachouri to continue. If Members cooperate, we will finish it early.

**Resolution Re. Unprecedented Rise in the Prices of Essential Commodities as a result of hike in administered prices —Contd.**

**श्री सुरेश पचौरी** (मध्य प्रदेश) माननीय : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा था कि जो आम उपभोक्ता के उपयोग में आने वाली आवश्यक वस्तुएं हैं उनके दामों में निरन्तर वृद्धि हो रही है, विशेषरूप से जो चावल, गेहूं, चीनी, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, उनकी कीमतों में जब निरन्तर वृद्धि हो रही है तो उससे आम जनता को अनेकानेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि सरकार समय रहते समुचित कदम उठाए ताकि आम जनता राहत की सांस ले सके । मान्यवर, जो एनुअल रेट आफ इनफलेशन था वह 10.2 प्रतिशत से बढ़कर इस साल के अप्रेल के सप्ताह तक 10.5 प्रतिशत हो गया है ।

जबकि ढाई साल पहले यह सरकार बनी थी, उस समय की स्थिति कुछ अलग थी । हमारे फॉरेन एक्सचेंज की भी स्थिति कुछ अलग थी, लेकिन आज यह आवश्यक हो गया है कि हम इस बात पर ध्यान दें कि रेट आफ इनफ्लेशन क्यों बढ़ रहा है ? इसके लिए एक यह सुझाव आया कि जो पैसा है उसको इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर में डायवर्ट किया जाए और कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं कि जो फॉरेन सेक्युरिटीज हैं, उसका ठीक ढंग से रिजर्व मनी के रूप में इनवेस्टमेंट किया जा सके । लेकिन इस बारे में भी कोई कदम नहींउठाए जा सके । फिर यह सुझाव सामने आया कि जो महत्वपूर्ण आयटम्स हैं, जैसे शक्कर है, एडीबल आॅइल है, कपास है इनका इम्पोर्ट किया जाए । उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि सरकार ने इस दिशा में पहल की है । सरकार ने क्या-क्या कदम इस संबंध में उठाए हैं, इसका ब्यौरा हमारे सामने है कि सरकार ने क्लोजली यह देखने के लिए कि मूल्यों में वृद्धि न हो सके इसका मानीटरिंग करने के लिए एक कमेटी बनायी है जिसमें कि सम्बंधित विभाग के अफसरों को रखा गया है और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इन एसेंसियल कमोडिटीज की प्राइस नियंत्रण में कैसे रहे और उसके लिए क्या-क्या एदम उठाए जाएं । इस बारे में उन्होंने समय-समय पर कुछ मीटिंग्स की हैं । जैसे कि मैंने बताया एक हाय-लेवल कमेटी का गठन किया गया है जो कि समय समय पर प्राइस सिचुएशन का रिव्यू करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उपभोक्ताओं को कैसे राहत दी जा सके और साथ ही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी किस ढंग से मजबूत किया जा सके ताकि उपभोक्ता को आम उपयोग की वस्तुएं मिल सकें और यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि एसेंसियल कमोडिटीज एक्ट, 1955 के तहत होर्डर्स और ब्लेक मार्केटियर्स के खिलाफ कार्यवाही की जाए । इस मीटिंग में इस बात की समीक्षा की गयी है ।

मान्यवर, जो शॉर्ट सप्लाय में है, जैसे पल्सेस, एडीबल आॅइल और शक्कर है, उसे इम्पोर्ट करने का सरकार ने जो निर्णय लिया है, वह निश्चित रूप से हमारे रेटा आॅफ इनफ्लेशन को नियंत्रण में लाएगा, ऐस मेरा विश्वास है । उपसभाध्यक्ष महोदय, ट्रांसपोर्टेशन में सुधार और आम उपभोक्ताओं को एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के लिए उपयोग में आने वाली वस्तुएं समय पर उपलब्ध हो सकें, यह भी सुनिश्चित किया गया है